CAPT. SATISH SHARMA: I have to...

MR. CHAIRMAN: Syed Sibtey Razi.

SYED SIBTEY RAZI: Mr. Chairman, Sir, it had been...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Let him reply. He is replying to my query.

CAPT. SATISH SHARMA: I will have to check up as to how much time it will take.

MR. CHAIRMAN: He will have to check up and find out. He said that. I heard that.

SYED SIBTEY RAZI: There has been concern in the country about petroleum and natural gas.

MR. CHAIRMAN: Please be very brief.

SYED SIBTEY RAZI: We were waiting that in the near future we would be self-reliant in this field. I would like to know from the hon. Minister if he is going to fix any accountability on the ONGC to find out why they have not been able to achieve their target. If they were over over-enthusiastic targets, then in future what alternative arrangement are you going to make?

MR. CHAIRMAN: I think the Minister has already given the substance of the answer. Would you like to respond?

श्री सैयद सिब्ते रजी : आप क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोल की जगह पर कुछ और एल0पी0जी0 वगैरह का प्रयोग करने के लिए आर0एंड डी0 का उपयोग कर रहे हैं जिससे इसकी खपत ट्रांसपोर्ट में कम हो सके और इसका रिप्लेसमेंट हो सके ?

†شری سید سبط رضی "جاری": آپ کیا یہ بتانے کی کرپا کریں گے کہ پٹرول کی جگہ پر کچھ اور ایل۔ پی۔ جی وغیرہ پریوگ کرنے کیلئے آر۔ اینڈ۔ ڈی کا اپیوگ کر رہے ہیں جس سے اس کی کھپت ٹرانسپورٹ میں کم ہو سکے اور اس کا ریپلیسمنٹ ہو سکے۔

MR. CHAIRMAN: That is a different question.

CAPT. SATISH SHARMA: It is not relevant to this question.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 462.

वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये प्राकृतिक वनों के इस्तेमाल को रोकने के लिये गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन

***462. श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटू भाई पटेल :*

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक वनों का उपयोग रोकने के वास्ते गैर सरकारी संगठनों से अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार वनों के दोहन, विशेषकर वृक्षों की कटाई को रोकने पर विचार कर रही है जिससे कि पर्यावरण संतुलन बना रहे तथा वनों के आस-पास रहने वाले आदिवासियों को भी वन-उपज से भरपूर लाभ मिल सके

†[ ] Transliteration in Arabic script.

*सभा में यह प्रश्न श्री छोटूभाई पटेल द्वारा पूछा गया ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No specific representation has been received from any of the private organisations to check the use of natural forest for commercial purposes.

(b) The Government is fully aware of the need for scientific and sustainable management of the Natural Forests.

(c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(c) The various steps taken by the Government to ensure preservation and sustainable exploitation of forest in order to maintain environmental balance and ensure welfare of tribals residing in around are:—

(i) National Forest Policy 1988 lays more emphasis on conservation of forest. There are specific provisions for protection of forest from grazing, fires and encroachement.

(ii) Forest Conservation Act was enacted in 1980 to check diversion of forest. There are specific proposes. The act has been made more stringent by an amendment in 1988.

(iii) A centrally sponsored scheme is under implementation to help the States to develop infrastructure for protection of forests.

(iv) A 100 per cent centrally sponsored scheme has been launched in 1992-93 to associate Scheduled Tribes in regeneration of degraded forests with the aim of improving bio-mass resurce base.

(v) Another 100 per cent Centrally Sponsored "Beneficiary Oriented Scheme for Tribal Development" is being implemented, which assists in rehabilitation of tribal and other families affected under relocation plans of the Project Tiger Areas, National Parks and Wildlife Sanctuaries.

(vi) Efforts have been taken to give a renewed thrust upon afforestation works from seventh plan period.

(vii) States|Union Territories have been advised to involve village communities and voluntary agencies to ensure protection and regeneration of degraded forest lands.

श्री छोटू भाई पटेल : सभापति जी, हमारे देश में जितना टोटल किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया है इसमें 19.49 प्रतिशत फारेस्ट एरिया है । विकासशील देशों की तरफ हम देखें तो हर साल हम 2.3 प्रतिशत फारेस्ट लैड को गवां रहे हैं। नेपाल के बाद हमारा दूसरा नम्बर आता है । इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं कि हमारे देश में चाहे कुमाऊं का जंगल हो, चाहे तराई का जंगल हो, चाहे अलमोड़ा का जंगल हो, चाहे वेस्टर्न घाट्स हों या डेंस फारेस्ट्स हों, इन क्षेत्रों में हर साल जंगलों की कटाई हो रही है । इससे हमारे देश में और दुनियां में इकोलोजिकल इम्बेलेंस हो रहा है जिससे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि इल्लीगल टिम्बर ट्रेड प्रेक्टिस जो हो रही है उसको दूर करने के लिए सरकार की ओर से कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं । मेरा सवाल नम्बर दो यह है....

MR. CHAIRMAN: Part two you can ask in the second supplementary please. The Minister may kindly answer.

श्री छोटू भाई पटेल : पार्ट बी सर, हमारे जो डेंस फारेस्ट हैं, ओपन फारेस्ट हैं और हमारे मैनग्रोज फारेस्ट हैं इनमें से कितना एरिया नान फारेस्ट एरिया में कनवर्ट किया जा चुका है ?

SHRI KAMAL NATH: Sir, the hon. Member is very correct that there are severe ecological imbalan-

ce and effects on the environment by deforestation which is taking place. Between 1951 to 1980, that is, prior to the enactment of the Forest Conservation Act, 4.32 million hectares were diverted. This situation came under control only after the enactment of the Forest Conservation Act. From the date of enactment of the Forest Conservation Act till 28th February, 1993, 3,03,201 hectares of land have been diverted. The deforestation and diversion which took place has been somewhat contained, I think, very largely contained. We can see this when we make a comparison between the various figures.

Sir, in the satellite imagery assessment, we find that between 1987-89, there has been an increase, for the first time, in the history of the country in our forest by about 28,000 hectares per annum. The hon. Member wanted to know, what is the rough average of the diversion which is taking place. Sir, the average diversion which took place was roughly about 25,000 hectares per annum since the enactment of Forest (Conservation) Act, 1980.

So far as afforestation is concerned, again there has been an improvement between the Sixth Plan period and the Seventh Plan period. In the Sixth Plan period the afforestation which took place was 46.5 million hectares. In the Seventh Plan peirod the afforestation which took place was 88.85 lakh hectares.

श्री छोटू भाई पटेल : सभापति जी, वनों के विकास के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य रखे गये थे और हमारी उपलब्धि क्या रही है ? इसके लिए क्या सरकार ने कोई मोनिटेरिंग एजेंसी रखी है या नहीं रखी है ? उद्योगों और बिल्डिंग्ज में लकड़ी को बचाने के लिए क्या सरकार के पास कोई टेक्नोलोजीकल आल्टरनेटिव है या नहीं है ?

SHRI KAMAL NATH: Sir, as far as the steps to have alternatives is concerned; we are promoting substitutes for timber. The demand for timber in the country continues. But steps are being taken. Fiscal incentives have been given to promote substitution of timber. At the same time; the demands of population and development continue. The demands of agriculture continue. And, steps have been taken to make people aware of the effects of diversion of forest land and afforestation on ecology, environment and on the daily lives of people.

श्रीमती सत्या बहिन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना और इसको कम प्रभावी मानने के कारण 1988 में इसको संशोधन करके और कठोर बनाया गया । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में अगर कोई गरीब आदिवासी थोड़ी सी भी लकड़ी अपने घर के लिए काटता है तो उसके ऊपर यह कानून कठोरता से लागू होता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मध्य प्रदेश—जहां से माननीय मंत्री जी स्वयं आते हैं, के बस्तर जिले में और उड़ीसा के कोरापुट जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, वहां पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई और मैं समझती हूं बड़े औद्योगिक घरानों को वन आबंटित किए गए हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को वन आबंटित किए गए हैं ? यदि हां, तो किस प्रयोजन से किए गए हैं, कितने किए गए हैं, कब किए गए हैं और कितनी अवधि के लिए किए गए हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : क्यों किए गए हैं?

श्रीमती सत्या बहिन : और क्यों किए गए हैं ?

SHRI KAMAL NATH: Sir, there have been reports of illegal felling of trees. That is not very true. In Bastar, there were reports of illegal felling of trees. An inquiry was instituted and in some cases, it was proven to be true. As far as giving

forest to industry is concerned, it is not within the purview of the Forest Conservation Act or within the purview of our National Forest Policy. Therefore, the question of any forest land having been given or being given to industry does not arise.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : सभापति महोदय, चूंकि वन भूमि का अधिकांश स्वामित्व राज्य सरकारों का है, उन्हीं के ऊपर वनों के संरक्षण की मुख्यत: जिम्मेदारी भी रहती है । 1988 के बाद वन संरक्षण अधिनियम को और कठोर बनाया गया लेकिन फिर भी जिस तरह से वनों का निरंतर कटान और वन भूमि का बृहत्तर प्रयोजनों के लिए उपयोग बढ़ता जा रहा है, इस बारे में मैं सभापति जी के माध्यम से सीधा तीन मुद्दों पर जानना चाहता हूं ।

(अ) केन्द्रीय वन संरक्षण बल का गठन आप करना चाहते हैं या नहीं जिससे कि वन कटान के मामलों का, आप सीधे-सीधे उनका संरक्षण कर सकें ? और 1991–92 में कितने अवैध कटान के मामले राज्यवार दर्ज हुए हैं ?

(ब) सामाजिक वानिकी के विकास और संरक्षण के लिए आप राज्य सरकारों को धन देते हैं । 1990–91 और 1991–92 में कितनी राज्यवार सहायता आपने प्रदान की है ? और यह परती भूमि जो है, कृषि के लिए पट्टे लगातार दिए जा रहे हैं ग्रामीण सभाओं के द्वारा, आप उनको रोकने के लिए कोई योजना या कार्यक्रम इसके लिए बना रहे हैं कि जो कृषि योग्य भूमि है या कृषि योग्य भूमि नहीं है, उस पर वन लगाने के लिए पट्टे दिए जाएं न कि कृषि के लिए पट्टे दिए जाएं ताकि देश में पर्यावरण संतुलन बना रहे ?

अंतिम (स) वनों की सुरक्षा के लिए, राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आप लागू करने जा रहे हैं । इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या विशेष बातें हैं और इसको आप कब से लागू करना चाहते हैं ?

SHRI KAMAL NATH: Sir, where the question of amendment of the Forest Conservation Act is concerned, it was considered in 1988. Currently, we are trying to see how it can be strengthend and on the basis of the experience we had, we are trying to see what kind of amendment is required. This matter is just being considered and there is nothing as such on the anvil.

Sir, where the question of diversion of forest land is concerned and whether we are giving any kind of title deeds to the farmers for agriculture or for farm forestry this does not arise because forest land is not given to anybody either to grow trees or for agricultural purposes. We have been trying to promote the scheme of agro-forestry and farm forestry on non-forestry wasteland, on land which does not come within the purview of the Forest Conservation Act. So we are trying to do this through various programmes.

Where the question of statistics is concerned, the hon. Member wanted to know as to what amount has been given in the area of social forestry to the various States; I shall send it to the hon. Member separately.

श्री यशवन्त सिन्हा : सर, हमारे नौजवान दोस्त मंत्री महोदय बहुत ही गतिशील मंत्रियों में हैं और रिश्रो से लेकर मांट्रियल तक इन्होंने धावा बोला है लेकिन मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका जो प्रभाव है वह शायद राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पा रहा है और इसलिए शायद जिस तरह से वनों का विकास होना चाहिए या वन जो नष्ट हो रहे हैं, उनमें जो रोकथाम होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है । मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारी वन संपदा बहुत ही अच्छी थी और धीरे-धीरे कटते-कटते वह समाप्त हो गई है । तो इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए क्या आपने कोई विशेष योजना बनाई है, खास-खास क्षेत्रों के लिए ।

यहां मैं खास तौर से पलामू का जिक्र करना चाहता हूं, बिहार में, जहां पर कि अब महुआ के वृक्ष छोड़कर, जहां लाख की खेती होती है, पलाश के ऊपर, दूसरा कोई वृक्ष नहीं बचा । वहां पर बहुत घना जंगल थ । तो इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए क्या आप राज्य सरकारों के साथ मिलकर विशेष योजना बनाएंगे, जो समेकित हो, कांप्रिहैंसिव हो और जिसमें हर प्रकार के पहलू को ध्यान में रखते हुए आप वहां पर वन संपदा को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठायेंगे ?

SHRI KAMAL NATH: Sir, I share the hon. Member's concern about forestry in India. But one of the constraints has been meagre financial allocation. In the Eighth Plan, we have an allocation of Rs. 4082 crores—Rs. 525 crores in the Central sector and Rs. 3,557 crores in the State sector. This is roughly one-third of what is required to take on forestry in a big way. Sir, through you, I would also like to inform the hon. Member that this degradation which was taking place, this afforestation which was taking place, has been reversed and I think, perhaps, we are the only country in the world, which has afforested for the first time in the year 1991-92 two million hectares approximately and these are not figures which have been planted in the files and trees not planted on the ground. I have subjected them to check by the NGO's by retired servicemen and we have got a feedback on the authenticity of these figures. We are making efforts in this regard. The hon. Member specially mentioned the case of Palamau. I shall certainly look into that. There is a focus on our most sensitive forest areas, in our ecologically sensitive areas. These have been segregated. We have schemes, both under our existing projects, and those which are linked with bilateral and multilateral funding schemes.

Signing of MOU between India and Oman

*463. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three separate memoranda of understanding dealing with the setting up of refineries and for the supply of the Natural Gas have been signed between India and Oman; and

(b) if so, what are the details thereof and the locations of the refineries proposed to be set up?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) Yes, Sir.

(b) Two of these relate to the setting up of two joint venture refineries, each with a capacity of 6 MMTPA, one with HPCL in Western India and the other with RPCL in Central India. Another M.O.U. relates to exploration of possibilities of supply of Natural Gas from OMAN and other sources through a pipeline to India.

SHRI SURESH KALMADI: Sir, I think what happened in the case of Oman is a good omen for the country The signing of the MOU expeditiously for a 1,400 kilometer gas pipeline is indeed a good sign. I would like to know by what time the feasibility study would be completed and what the costs would be. Since you have involved the HPC and Bharat Petroleum in these refineries, I would like to know whether the public would also be taking part in these in equity terms. I would also like to know whether the supply would be sufficient or you would still have to go to other Gulf countries like Qatar, Iran, etc. for similar projects so that we have enough supply of crude and gas.